RDI कोष: जोखिमपूर्ण नवाचार और सार्वजनिक धन का भरोसा

अगस्त 2026 | समाचार संदर्भ: 19 अगस्त 2026 | GS-III / GS-IV

उन्नत तकनीक प्रयोगशाला से बाजार तक पहुँचने में समय और अनिश्चितता से गुजरती है। ऐसे काम के लिए धैर्यपूर्ण पूंजी उपयोगी हो सकती है। लेकिन जब सार्वजनिक धन निजी कंपनियों को सहारा देता है, तो चयन की निष्पक्षता, विशेषज्ञता और हित-संघर्ष के नियंत्रण को साथ मजबूत करना पड़ता है।

खबरों में क्यों

19 अगस्त 2026 की सरकारी समीक्षा में अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष के वितरण, हित-संघर्ष सुरक्षा उपायों और रणनीतिक क्षेत्रों के विस्तार पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा कि सुरक्षा उपाय मौजूद हैं और जरूरत होने पर सुझावों के आधार पर उन्हें मजबूत किया जा सकता है। इससे पहले अगस्त की एक जाँच-रिपोर्ट ने चयनित कंपनियों और समिति सदस्यों के निवेश-संबंधों पर प्रश्न उठाए थे। रिपोर्ट में हित की घोषणा और संबंधित मूल्यांकन से अलग रहने की बात भी दर्ज थी; निवेश-संबंध को अपने-आप सिद्ध अनियमितता नहीं कहा जा सकता।

धैर्यपूर्ण पूंजी क्यों?

धैर्यपूर्ण पूंजी ऐसा वित्त है जो तकनीक के विकसित होने और बाजार बनने के लंबे समय को ध्यान में रखता है। इससे तुरंत आय न देने वाले उपयोगी अनुसंधान को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। फिर भी तकनीकी विफलता का जोखिम बना रहता है; सार्वजनिक समर्थन सफलता की गारंटी नहीं है।

मुख्य तथ्य

कोष का वित्तीय स्वरूप: ₹1 लाख करोड़ के RDI ढाँचे में दीर्घकालिक ऋण, इक्विटी और दोनों के संयोजन की व्यवस्था है। इसे केवल अनुदान या केवल ऋण की योजना कहना गलत होगा। कार्यान्वयन दिशानिर्देश अनुदान और अल्पकालिक ऋण को इस सहायता-पथ से अलग रखते हैं।

अनुसंधान से व्यावसायीकरण: दिशानिर्देशों में तकनीकी तत्परता स्तर TRL-4 से आगे की पात्र तकनीक पर जोर है। TRL तकनीक की परिपक्वता बताने का पैमाना है; प्रयोगशाला में सत्यापन और बाजार में सफल उपयोग एक ही चरण नहीं हैं।

वित्त और जवाबदेही की कड़ी: धन द्वितीय-स्तरीय कोष प्रबंधकों के माध्यम से पात्र संस्थाओं तक पहुँचता है। सामान्य वित्तीय सीमा आकलित परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक है; निर्धारित स्वीकृति से अपवाद संभव है। हित-संघर्ष घटाने के लिए खुलासे और निर्णय-प्रक्रिया संबंधी उपाय भी दिशानिर्देशों का हिस्सा हैं।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

योजना की स्थिति: 29 जुलाई 2026 का लोकसभा उत्तर

स्वीकृति और वितरण: PIB (29 जुलाई 2026) के अनुसार लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया गया कि प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (TDB) और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) को ₹1,000 करोड़ प्रत्येक, यानी कुल ₹2,000 करोड़ की सहायता स्वीकृत हुई है। इसमें से मार्च 2026 में TDB को ₹500 करोड़ वितरित हुए। हमारी गणना: स्वीकृत राशि ₹1 लाख करोड़ का 2 प्रतिशत और वितरित राशि 0.5 प्रतिशत है; ये अनुपात सरकार ने नहीं दिए।

TDB की परियोजनाएँ: PIB के अनुसार TDB ने 22 परियोजनाएँ स्वीकृत की हैं, जिनकी कुल लागत ₹4,744 करोड़ है और RDI कोष का समर्थन ₹2,192 करोड़। हमारी गणना: यह लागत का लगभग 46 प्रतिशत है और TDB को स्वीकृत ₹1,000 करोड़ से ₹1,192 करोड़ अधिक है। विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि यह अंतर कैसे जुड़ता है, इसलिए हम इसे केवल अस्पष्ट बताते हैं। BIRAC की 8 शॉर्टलिस्ट परियोजनाओं के साथ “₹390.35 करोड़” लिखा है, जो लागत है या समर्थन, पाठ से स्पष्ट नहीं। AIF और शेष FRO के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के विचाराधीन बताए गए हैं।

शब्दावली: मंत्रिमंडल की 1 जुलाई 2025 की विज्ञप्ति “₹1 लाख करोड़ का कोष” कहती है, जबकि इस उत्तर में “छह वर्षों में ₹1 लाख करोड़ का परिव्यय” है। हमें मंत्रिमंडल की विज्ञप्ति में अवधि का उल्लेख नहीं मिला। यह खंड केवल 29 जुलाई 2026 की स्थिति है; निर्णयों और आगे के वितरण से तस्वीर बदलेगी।

स्रोत: PIB, संसदीय प्रश्न: अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना (29 जुलाई 2026); PIB, मंत्रिमंडल ने RDI योजना को मंज़ूरी दी (1 जुलाई 2025)। दिशानिर्देश, SLFM समझौते और प्रश्न का मूल पाठ नहीं पढ़े गए; सभी आँकड़े सरकार के दावे हैं।

विशेषज्ञता और निष्पक्षता कैसे साथ रहें?

विशेषज्ञ नेटवर्क की दोहरी भूमिका: विशेषज्ञ तकनीक और बाजार की संभावना पहचान सकते हैं। उन्हीं के निवेश-संबंध निष्पक्षता पर प्रश्न भी उठा सकते हैं। संबंध छिपाने के बजाय उसका खुलासा और उचित प्रबंधन जरूरी है।

केवल बैठक से हटना पर्याप्त नहीं: हित बताना और संबंधित निर्णय से अलग रहना महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। इनके साथ स्वतंत्र मूल्यांकन, दर्ज कारण और प्रक्रिया की जाँच यह भरोसा मजबूत कर सकते हैं कि निर्णय अनुचित प्रभाव से मुक्त रहा।

तेजी और सावधानी: धन देने में देरी नवाचार को रोक सकती है, जबकि कमजोर जाँच सार्वजनिक संसाधन को जोखिम में डालती है। स्पष्ट समय-सीमा और जोखिम के अनुरूप जाँच से दोनों उद्देश्यों में संतुलन खोजा जाए।

विश्लेषण और आगे की राह

चयन में तकनीकी योग्यता, व्यावसायिक संभावना और सार्वजनिक उद्देश्य के मानदंड पहले स्पष्ट हों। समिति सदस्यों के प्रत्यक्ष तथा प्रतिस्पर्धी हितों का खुलासा, संबंधित निर्णयों से अलग रहने का रिकॉर्ड और स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा उपयोगी हैं। सहायता चरणबद्ध लक्ष्यों से जुड़ी हो, लेकिन शोध की स्वाभाविक अनिश्चितता को भ्रष्टाचार के समान न माना जाए। परिणाम की समीक्षा में स्वदेशी क्षमता, तकनीक का उपयोग और अतिरिक्त निजी निवेश देखें। एक असफल परियोजना और अनुचित चयन अलग समस्याएँ हैं, जिनकी जाँच भी अलग कसौटी पर होनी चाहिए। पारदर्शिता में वैध व्यावसायिक गोपनीयता का ध्यान रखते हुए सार्वजनिक धन के उपयोग का पर्याप्त आधार सामने आए।

अवधारणा में अंतर

हित-संघर्ष ऐसी स्थिति है जिसमें निजी हित सार्वजनिक निर्णय को प्रभावित कर सकता है; यह हर मामले में सिद्ध भ्रष्टाचार नहीं है। इसी तरह वित्त स्वीकृत होना, धन वितरित होना और तकनीक सफल होना अलग चरण हैं।

मेंस दृष्टि

उत्तर में नवाचार को अनियंत्रित सब्सिडी या हर जोखिम को दुरुपयोग न मानें। धैर्यपूर्ण पूंजी की जरूरत और सार्वजनिक वित्त की नैतिक जवाबदेही दोनों पर तर्क दें।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

सार्वजनिक वित्त से समर्थित उन्नत तकनीकी नवाचार में विशेषज्ञ भागीदारी आवश्यक है, किंतु हित-संघर्ष का जोखिम भी रहता है। पारदर्शिता, स्वतंत्र मूल्यांकन और समयबद्ध वित्त के बीच संतुलन पर विवेचना कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: उन्नत तकनीकी अनुसंधान में लंबी अवधि, अनिश्चित परिणाम और धैर्यपूर्ण पूँजी की जरूरत रखें; सार्वजनिक वित्त में विशेषज्ञता के साथ निष्पक्ष चयन की जिम्मेदारी बताएँ।

मुख्य भाग में: विशेषज्ञ तकनीक तथा बाजार की संभावना पहचानते हैं, पर उनके निवेश-संबंध हित-संघर्ष भी पैदा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष और प्रतिस्पर्धी हितों का खुलासा, संबंधित निर्णय से अलगाव, स्वतंत्र मूल्यांकन और दर्ज कारण रखें। जाँच की स्पष्ट समय-सीमा से देरी घटाएँ और सहायता चरणबद्ध लक्ष्यों से जोड़ें। शोध की स्वाभाविक असफलता को अनुचित चयन या सिद्ध भ्रष्टाचार से अलग करें; स्वीकृति, वितरण तथा तकनीकी सफलता एक घटना नहीं हैं।

निष्कर्ष में: स्वदेशी क्षमता, तकनीकी उपयोग और अतिरिक्त निजी निवेश से परिणाम परखें। वैध व्यावसायिक गोपनीयता के साथ सार्वजनिक धन के निर्णयों का पर्याप्त आधार सामने आए; गति और जोखिम स्वीकारें, पर चयन की नैतिक जवाबदेही कम न करें।

स्रोत

- 19 अगस्त: वितरण और हित-संघर्ष पर सरकारी समीक्षा
- ANRF: RDI कार्यान्वयन दिशानिर्देश
- 8 अगस्त: उठे प्रश्न, खुलासा और सरकार का प्रत्युत्तर

याद रखें: नवाचार का जोखिम स्वीकार करें; चयन की निष्पक्षता और सार्वजनिक जवाबदेही कम न करें।